



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2243]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 2010/कार्तिक 6, 1932

No. 2243]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2010/KARTIKA 6, 1932

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2010

का.आ. 2659(अ).—माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय

सरकार को तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य के मध्य सन् 2006 का मूल वाद सं. 3 के मामले में अपने आदेश तारीख 18 फरवरी, 2010 और तारीख 29 मार्च, 2010 द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा माननीय डॉ. ए. एस. आनंद, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति को अध्यक्ष, अध्यक्ष के परामर्श से तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य से एक सदस्य और अध्यक्ष के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो तकनीकी सदस्यों को जो विवाद से संबंधित न हों, से मिलकर बनने वाली सशक्त समिति का गठन करने के लिए निर्देशित किया था।

और, सशक्त समिति, उसके समक्ष वाद के पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी विवादकों पर, बिना उन विवादकों तक सीमित किए हुए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे, सुनवाई करनी थी और गठन से छह मास के भीतर तथा संभवशीर्ष, रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और, सशक्त समिति, अधिसूचना सं. का.आ. 827(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2010 द्वारा गठित की गई थी;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन् 2006 का मूल वाद सं. 3 के मामले में अपने तारीख 20 सितम्बर, 2010 के आदेश द्वारा यह आदेश किया कि समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशों का अनुपालन करने के लिए, सशक्त समिति की अवधि को 30 अक्टूबर, 2010 से छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित करती है।

[फा. सं. 11/2/2010-बीएम]

जी. मोहन कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2010

S.O. 2659(E).—Whereas in the matter of Original Suit No. 3 of 2006, between State of Tamil Nadu V/s. State of Kerala, the Hon'ble Supreme Court *vide* its Orders dated 18th February, 2010 and 29th March, 2010 directed the Central Government to set up by notification in the Official Gazette, an Empowered Committee, comprising of Hon'ble Dr. A.S. Anand, former Chief Justice of India as the Chairman, one Member each to be nominated by the State of Tamil Nadu and State of Kerala, in consultation with the Chairman, and two technical experts, not connected with the dispute, to be nominated by the Central Government, in consultation with the Chairman;

And whereas the Empowered Committee was to hear to the parties to the suit on all issues raised before them without being limited to issues that have been raised before Hon'ble Supreme Court and Committee was to furnish a report, as far as possible, within a period of six months from its constitution;

And whereas the Empowered Committee was constituted *vide* notification number S.O. 827(E), dated the 30th April, 2010;

And whereas the Hon'ble Supreme Court in the matter of original Suit No. 3 of 2006, *vide* its Order dated the 20th September, 2010 ordered that the time for the submission of the report by the Committee is extended by a further period of six months;

Now, therefore, for implementing the said directions of the Supreme Court, the Central Government hereby extends the terms of Empowered Committee for a further period of six months with effect from the 30th October, 2010, onwards.

[F.No. 11/2/2010-BM]

G. MOHAN KUMAR, Addl. Secy.